Publication	**Hindustan Times**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	City pg 2
CCM	N/A		

RICM holds event on empowering farmers

RICM holds event on empowering farmers

CHANDIGARH : A two-day national conference, starting Thursday, on "Building a Viksit Bharat: Transforming Rural Economies through Cooperation, Farmer Empowerment and Growth" is being organised at the Regional Institute of Cooperative Management (RICM), Chandigarh. The meet aims to foster innovative practices, strategies and collaboration to empower rural communities and advance growth. **HTC**

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Amar Ujala**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	5
CCM	N/A		

प्रदेश की पैक्स मॉडल के रूप में विकसित की जाएं : गुर्जर

प्रदेश की पैक्स मॉडल के रूप में विकसित की जाएं : गुर्जर

चंडीगढ़। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऑडिट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी ऑडिट प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफार्म पर संचालित होनी चाहिए। ब्यूरो

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Amar Ujala**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	City pg 1
CCM	N/A		

ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, सतत विकास के लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, सतत विकास के लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री और हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने किया शुभारंभ

माई सिटी रिपोर्टर

चंडीगढ़। सेक्टर-32 के क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में विकसित भारत का निर्माण : सहकारिता, किसान सशक्तिकरण और विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए ग्लोबल इनसाइट्स का लाभ उठाना और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई प्रथाओं, रणनीतियों और सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का उद्घाटन वीरवार को केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। गुर्जर ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सहकारी समितियां देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक लाख करोड़ का योगदान देंगी। उद्घाटन सत्र में दोनों नेताओं ने सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल मेरी समिति मेरा पटल लॉन्च किया। यह पोर्टल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर के सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, कौशल बढ़ाने और समाजीकरण को बढ़ावा देगा।

क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा व अन्य। स्रोत : आयोजक

सम्मेलन के दौरान आरआईसीएम ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-कृषि व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मेरी समिति मेरा पटल पोर्टल सहकारी समितियों की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। सरकार लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठा रही है।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Jagran**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	7
CCM	N/A		

देश में बनेंगी दो लाख नई सहकारी समितियां

देश में बनेंगी दो लाख नई सहकारी समितियां

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सहकारिता मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाई सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए • डीपीआर

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : अगले पांच वर्षों में देश में दो लाख नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें नौ हजार सहकारी समितियां पंजाब और 2500 हरियाणा में गठित की जाएंगी। पिछले चार महीने के दौरान देश में 15 हजार समितियों का गठन हो चुका है।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत निर्माण : सहकारिता के माध्यम से किसान सशक्तीकरण, विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्था' का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। सम्मेलन में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के

पांच साल में हरियाणा में 2500 और पंजाब में 9000 नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी

मार्गदर्शन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहकारिता मंत्रालय अहम भूमिका अदा करेगा। वर्ष 2021 में सहकारिता क्षेत्र में समावेशी युग की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले पांच साल में एक लाख ट्रिलियन का योगदान करते हुए विकसित भारत निर्माण अभियान में भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीते तीन साल में 60 पहल की गई हैं, जो देश की साढ़े आठ लाख सहकारी समितियों को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Jagran**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	City pg 2
CCM	N/A		

सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'मेरी समिति मेरा पटल पोर्टल' लांच

सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'मेरी समिति मेरा पटल पोर्टल' लांच

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के तहत क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आरआइसीएम) चंडीगढ़ में वीरवार को "विकसित भारत का निर्माण: सहकारिता, किसान सशक्तिकरण और विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

- विकसित भारत का निर्माण विषय पर आरआइसीएम चंडीगढ़ में शुरू हुआ सम्मेलन
- केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा पोर्टल समितियों का करेगा विकास
- पांच वर्ष में सहकारी समितियां देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक ट्रिलियन डालर का योगदान

सम्मेलन का उद्घाटन वीरवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल 'मेरी समिति मेरा पटल' लांच किया। यह पोर्टल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर की सहकारी समितियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, कौशल संवर्धन और समाजीकरण को बढ़ावा देना है। सहकारी समितियों की मान्यता, संवादहीनता और नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने में आने वाली अन्य समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि 'मेरी समिति मेरा पटल' पोर्टल सहकारी समितियों की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा, जो लाखों युवाओं को सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए आनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करना। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर की गई विभिन्न पहलों पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार बहुउद्देशीय एवं बहुराज्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना चाहती है।

आरआइसीएम में सहकारिता के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-पैक्स प्रमाण पत्र जारी करते केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा •पीआरओ

आरआइसीएम के प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू

आरआइसीएम ने एआइसीटीई के अनुमोदित प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-कृषि व्यवसाय प्रबंधन (पीजीडीएम-एबीएम) कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सहकारिता और कृषि में व्यावसायिक उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। संस्थान की राष्ट्रीय शोध पत्रिका "सहकारिता अनुसंधान" का भी विमोचन किया। संस्थान के निदेशक डा. राजीव कुमार ने कहा कि मंच विचारों के आदान-प्रदान व अनुभवों से सीखने का सअवसर प्रदान करता है।

Downloaded from
SAMVAD

Publication Jagmarg | **Language** Hindi
Edition Chandigarh | **Journalist**
Date 25/04/2025 | **Page no** 12
CCM N/A

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी सहकारिता: गुर्जर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी सहकारिता: गुर्जर

मजबूत होगा सहकारिता का भाव, पांच में दो लाख नए पैक्सों के गठन का लक्ष्य

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहकारिता मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वर्ष 2021 में सहकारिता क्षेत्र में समावेशी युग की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले पांच साल में 1 लाख ट्रिलियन का योगदान करते हुए विकसित भारत निर्माण अभियान में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा।

वीरवार को क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधक संस्थान सेक्टर-32 चंडीगढ़ द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन %विकसित भारत निर्माण-सहकारिता के माध्यम से किसान सशक्तिकरण, विकास व ग्रामीण में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और सहकारिता मंत्री डॅ. अरविंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय सम्मेलन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि संकल्प के साथ सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था, ताकि सहकारी समितियों देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकें।

गांव की मजबूती से ही मिलेगी देश को मजबूती: शर्मा

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि कृषि प्रधान देश है, यदि गांव मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का लक्ष्य हर गांव, हर किसान को समृद्ध बनाने का है, ताकि हर सहकारी संस्था आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। देश को पहला सहकारिता क्षेत्र का विश्वविद्यालय मिलने से इस क्षेत्र में कुशल श्रमबल की उपलब्धता बढ़ेगी और हर साल 8 लाख युवा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर शोध-अनुसंधान कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता विभाग डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज जैसी तकनीक को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया पौधरोपण

राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारम्भ अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर व प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाई गई सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उनके उत्पादों की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया व आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने की जानकारी सांझा की गई। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय से पवित्र कुमार, हरियाणा सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, निदेशक कपिल मीणा, निदेशक कुमार रामकृष्ण, हरियाणा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, पंजाब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार विमल सेतिया तथा हैफेड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**City Darpan**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर केंद्रित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर केंद्रित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा रहे शामिल

संवाददाता

चंडीगढ़

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

श्री गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऑडिट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी ऑडिट प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की पैक्स की समस्याओं की पहचान कर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि अन्न भंडारण योजना को भी गति देने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

श्री गुर्जर ने जीवन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए ड्रग लाइसेंस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल केवल 8 केंद्रों को लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जबकि आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना से जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त, 9 एफपीओ का पंजीकरण किया जा चुका है और उनकी वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है, ताकि उनके व्यापार को विस्तार मिल सके।

बैठक में राज्य के सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए और किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर 85% तक की गारंटी का लाभ सुनिश्चित किया जाए। पैक्स को माइक्रो एटीएम सुविधा से जोड़कर ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे सहकारिता की भावना जन-जन तक पहुँच सके। बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 2500 नए पैक्स खोलने का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेडरेशन से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि सभी हितधारकों को समान सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की श्रेष्ठ सहकारी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा में लागू करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने ह्वीटा पार्लरह्न को आधुनिक स्वरूप में विकसित कर शहरी क्षेत्रों की सोसायटियों में स्थापित करने के निर्देश दिए। मंडियों के नियमित निरीक्षण को अनिवार्य मानते हुए उन्होंने कहा कि इससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते हुए प्रदेश की सहकारी प्रणाली को मजबूती प्रदान करें। बैठक के दौरान उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पैक्स के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली 25 सेवाओं को प्रभावी, सरल और निर्बाध रूप से लागू किया जाए, ताकि आमजन को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष और सुगम लाभ मिल सके।

इस बैठक में सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री राजेश जोगपाल, हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री मुकुल कुमार, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. राजीव कुमार सहित सहकारिता विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Downloaded from SAMVAD

Publication	**Daily World**	**Language**	English
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	4
CCM	N/A		

Union minister Gurjar reviews progress on digitisation and expansion of cooperatives

Union minister Gurjar reviews progress on digitisation and expansion of cooperatives

CHANDIGARH Union Minister of State for Cooperation Krishan Pal Gurjar on Thursday held a review meeting to discuss the progress on digitisation and expansion of the cooperative societies in Haryana. Several important decisions were made to make cooperative institutions transparent, effective, and technologically capable, an official statement said. Gurjar asked the concerned officials to ensure that the audit process should be entirely online to digitally empower the functioning of cooperative institutions.

He said that issues faced by the Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the state should be identified, and PACS should be developed as model institutions with concrete plans to enhance their income.

Gurjar also asked for speedy completion of the drug licensing process for setting up "Jeevan Aushadhi Kendras".

Emphasising on the modernization of state cooperative banks during the meeting, he stated these banks should be made technologically advanced and that farmers should get the benefit of loan guarantee of up to 85 per cent.

Haryana Cooperation Minister Arvind Sharma also asked the officials to ensure that the target of opening 2,500 new PACS set by the state government should be completed on a priority basis.

Meanwhile, at another event, Gurjar said that the Union Ministry of Cooperation will play a pivotal role in revitalising the rural economy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.

Gurjar, along with Haryana Cooperation Minister Sharma, inaugurated a two-day national conference titled 'Developing Developed India: Farmer Empowerment, Development, and Rural Progress through Cooperatives'.

The event is being organized by the Regional Institute of Co-operative Management here.

Gurjar stated that the Ministry of Cooperation, established by Prime Minister Modi in 2021 with the vision of "prosperity through cooperation", has since launched around 60 significant initiatives under the leadership of Union Minister for Cooperation Amit Shah.

These initiatives aim to transform India's 8.5 lakh co-operative societies into engines of rural and national growth, he said.

He further added that standardised bylaws are being developed to unify and strengthen cooperative societies, and computerization of PACS is underway to boost operational efficiency.

Making PACS multi-functional by integrating 25 types of services will unlock greater self-employment opportunities for members, thus benefiting communities and the nation at large.

Looking ahead, the government plans to establish 2 lakh new cooperative societies in the next five years, of which 15,000 have already been formed in the past four months, he said.

Gurjar said that in the next five years, 9,000 new cooperative societies will be formed in Punjab and 2,500 in Haryana, further reinforcing the sector.

Speaking on the occasion, Sharma underscored the importance of cooperation in strengthening India's socio-economic fabric, particularly in rural and agrarian contexts.

"A strong village is the foundation of a strong nation," he said, adding that the cooperative sector is key to realising Prime Minister Modi's vision of a developed India by 2047.

The event began with a two-minute silence in memory of those who lost their lives in the terrorist attack in Pahalgam. / PTI /

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Jagat Kranti**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	12
CCM	N/A		

सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण और विस्तार पर हुई समीक्षा

सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण और विस्तार पर हुई समीक्षा

जगत क्रान्ति ⏭ राकेश गुप्ता

चण्डीगढ़ : केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज चण्डीगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऑडिट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी ऑडिट प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की पैक्स की समस्याओं की पहचान कर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और उनकी

आय बढ़ाने की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि अन्न भंडारण योजना को भी गति देने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। श्री गुर्जर ने जीवन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए ड्रग लाइसेंस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल केवल 8 केंद्रों को लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जबकि आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना से जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त, 9 एफपीओ का पंजीकरण किया जा चुका है और उनकी वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है, ताकि उनके व्यापार को विस्तार मिल सके। बैठक में राज्य के सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए और किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक की गारंटी का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Jalandhar Breeze**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	3
CCM	N/A		

भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी युनिवर्सिटी का महत्व

भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी युनिवर्सिटी का महत्व

भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी युनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी के लिए विधेयक का संसद में पारित होना भारतीय सहकारी आंदोलन की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसका 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान संपन्न होना इसके महत्व को और बढ़ाता है। जैसा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, यह युनिवर्सिटी "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने में एक शक्तिशाली माध्यम बनने के लिए तैयार है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन का घर है, जिसमें 800,000 से ज़्यादा सहकारी समितियाँ और 287 मिलियन सदस्य शामिल हैं। रोटी, कपड़ा से लेकर मकान तक की जरूरतों के लिए लोगों के दैनिक जीवन में गहराई से समाहित सहकारी समितियाँ सिर्फ़ आर्थिक संस्थाएँ नहीं हैं; वे समुदाय-संचालित विकास, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस क्षेत्र के लिए एक नई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का संकेत दिया, जिसका उद्देश्य इसकी पहुँच का विस्तार करना, इसकी दक्षता में सुधार करना और इसे समावेशी विकास की आधारशिला के रूप में एकीकृत करना है।

सहकारिता मंत्रालय ने सराहनीय कदम उठाए हैं: 67,390 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए ₹2,516 करोड़ आवंटित करना, 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में PACS को सक्षम करने के लिए 32 राज्यों में मॉडल उपनियमों को लागू करना, 2 लाख नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (MPACS) बनाने का लक्ष्य रखना, 1,100 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को समर्थन देना और 44,000 PACS को सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) में बदलना। कर प्रोत्साहन, आसान ऋण और विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधा सहकारी समितियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। बीज, निर्यात और जैविक उत्पादों के लिए तीन नए राष्ट्रीय महासंघों की स्थापना इस बात का संकेत है कि सहकारी समितियों को भारत के विकास के प्रमुख एजेंट के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

परन्तु, अपने विस्तार और पहुंच के बावजूद, सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की अवरचना आंशिक, अविकसित और असमान रूप से वितरित है। प्रबंधकीय और प्रशासनिक से लेकर तकनीकी और परिचालन तक योग्य पेशेवरों की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। मौजूदा कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है । इन कर्मचारियों में से कई के पास नियमित प्रशिक्षण या शिक्षा के अवसरों तक पहुंच नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन और

जालंधर ब्रीज

बालासुब्रमण्यम अय्यर
(क्षेत्रीय निदेशक, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस एशिया एंड पैसिफिक)

संस्थागत सामंजस्य के बिना, यह क्षेत्र अपनी क्षमता का पूरी तरह से लाभ नहीं ले सकता है या अपने विकास को बनाए नहीं रख सकता है। सहकारी आंदोलन में नई और युवा पीढ़ियों को आकर्षित करने की भी सख्त जरूरत है - ऐसे व्यक्ति जो न केवल पेशेवर हों बल्कि सहकारी मूल्यों से प्रेरित हों और क्षेत्र में नवाचार करने के लिए आतुर हों। यहां, त्रिभुवन सहकारी युनिवर्सिटी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है: शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक केंद्र के रूप में सेवा करके जो नई पीढ़ी के सहकारी नेताओं को बढ़ावा देते हुए सभी स्तरों पर उनकी क्षमता का निर्माण कर सकेगा ।

अमूल मॉडल के वास्तुकार, दूरदर्शी त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर, और भारत की डेयरी सहकारी क्रांति के उद्गम स्थल आनंद में स्थित यह युनिवर्सिटी एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है, साथ ही यह एक रणनीतिक हस्तक्षेप भी है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (IRMA) का चयन - एक ऐसा संस्थान जिसने दशकों से सहकारी प्रबंधन शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है - इस युनिवर्सिटी की नींव के रूप में व्यावहारिक और प्रेरणादायक दोनों है। आनंद में IRMA को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नामित किए जाने के साथ, यह युनिवर्सिटी सहकारी उद्यमों की चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए सुसज्जित पेशेवरों को तैयार करने की एक मजबूत विरासत का निर्माण करेगा।

युनिवर्सिटी का विज़न सिर्फ़ औपचारिक प्रबंधन डिग्री तक सीमित न होकर काफी विस्तृत है । यह प्राथमिक और माध्यमिक सहकारी समितियों के बोर्ड सदस्यों, सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों, और नैतिक, सस्टेनेबल और समावेशी व्यवसाय मॉडल में रुचि रखने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तक अपनी पहुँच बढ़ाएगा। इसके लिए, युनिवर्सिटी लचीले शिक्षण मॉड्यूल, प्रमाणन कार्यक्रम, डिग्री कार्यक्रम, डिजिटल पहुँच प्रदान करेगा और क्षेत्र-आधारित ऐसे शोध का जरिया बनेगा, जिनसे स्व-सहायता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पारस्परिक जिम्मेदारी के सहकारी मूल्यों का लाभ सभी को मिल सकेगा।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय ज्ञान मंच के रूप में भी काम कर सकता है, हितधारकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बना सकता है, साक्ष्य-आधारित नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और ग्रामीण वास्तविकताओं के अनुरूप नवाचारों का समर्थन कर सकता है। डेयरी, ऋण, आवास, मत्स्य पालन, कपड़ा आदि जैसे भारत के विविध सहकारी परिदृश्य में, विश्वविद्यालय एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित होगा जहां, शिक्षा, नीति निर्माता और सहकारिता से जुड़े विशेषज्ञ उन्नयन के नये पथ ईजाद कर सकेंगे। वैश्विक स्तर पर, सहकारी शिक्षा सहकारी आंदोलनों की सफलता का आधार रही है। 1844 में रोशडेल पायनियर्स के समय से ही, आचरण के मूल नियमों में मुनाफे का एक हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करना शामिल था। पाँचवाँ सहकारी सिद्धांत - शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना - आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य, नेता और समुदाय सहकारी मॉडल को समझें और उसका पालन करें। यह गहरी जड़ें जमाए बैठी शैक्षिक परंपरा ही है जो सहकारी शासन को बनाए रखती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और जवाबदेही को मजबूत करती है।

इस संदर्भ में, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी केवल एक शैक्षणिक संस्थान से कहीं अधिक होगा - यह सहकारी विकास के लिए एक राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान केंद्र बन सकता है, एक ऐसा स्थान, जहाँ प्रयोग और नीति का संगम हो और जहां नेतृत्व सीख से प्रेरित हो । नई दिल्ली में आयोजित ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से सहकारी समितियों को एकजुट करने, साझा मंच बनाने, आम चुनौतियों से निपटने और सामूहिक रूप से आगे का रास्ता तय करने में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऐसा ही एक मंच प्रदान करता है - जो संवाद को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहकारी समितियों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने में सक्षम है।

एक ऐसी दुनिया में जहाँ समावेशी, लोकतांत्रिक और सतत विकास सुनिश्चित करते आर्थिक मॉडल की मांग बढ़ रही है, भारत का सहकारी आंदोलन और अब इसका पहला सहकारी यूनिवर्सिटी न केवल प्रेरणा बल्कि दिशा भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय को सुलभ, नवोन्मेषी और प्रभावोत्पादक होना चाहिए, जो आंदोलन के हर स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा दे। नींव रखी जा चुकी है; अब समय आ गया है कि एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो उस दृष्टिकोण के योग्य हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है - एक ऐसा संस्थान जो आने वाली पीढ़ियों को सहकारिता की अविनाशी शक्ति के माध्यम से शिक्षित, सशक्त और ऊर्जावान बनाएगा - और यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी समितियाँ सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करें।

Downloaded from SAMVAD

Publication	**Jalandhar Breeze**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	4
CCM	N/A		

विकसित भारत का निर्माण' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आरआईसीएम चंडीगढ़ में हुआ उद्घाटन

‘विकसित भारत का निर्माण’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आरआईसीएम चंडीगढ़ में हुआ उदघाटन

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सहकारी समितियों के लिए डिजिटल पोर्टल "मेरी समिति मेरा पटल" लॉन्च किया

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के तहत क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आरआईसीएम) चंडीगढ़ में 24-25 अप्रैल के दौरान ‘विकसित भारत का निर्माण: सहकारिता, किसान सशक्तिकरण और विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। इसका उद्देश्य भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए वैश्विक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाना है। इसके साथ ही ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए नवीन प्रथाओं, रणनीतियों और सहयोग को बढ़ावा देना है। ‘मेरी समिति मेरा पटल’ पोर्टल का शुभारंभ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल ‘मेरी समिति मेरा पटल’ लॉन्च किया। यह पोर्टल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर की सहकारी समितियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, कौशल संवर्धन और समाजीकरण को बढ़ावा देना है तथा यह सहकारी क्षेत्र में भविष्य की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के रूप में कार्य करेगा। इससे सहकारी समितियों की मान्यता, संवादहीनता तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने में आने वाली अन्य समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Savera Times**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	2
CCM	N/A		

सहकारिता सम्मेलन में हुआ 'मेरी समिति मेरा पोर्टल' का शुभारंभ

सहकारिता सम्मेलन में हुआ 'मेरी समिति मेरा पोर्टल' का शुभारंभ

उन्होंने आज चंडीगढ़ में आयोजित सहकारिता सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें विकसित भारत में सहकारिता का योगदान विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मेरी समिति, मेरा पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि सहकारिता किसानों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से गुजरात में एक सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, जहां प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि पैक्स का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले इनमें सीमित कार्य होते थे, लेकिन अब 25 से अधिक सेवाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हरियाणा में 2500 नए पैक्स बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में सहकारिता का एक ट्रिलियन डॉलर हिस्सा होगा।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Savera Times**	**Language**	Hindi
Edition	Chandigarh	**Journalist**	
Date	25/04/2025	**Page no**	9
CCM	N/A		

सहकारी संस्थाओं को डिजीटल रूप से सशक्त बनाने में ऑडिट प्रक्रिया को ऑनलाइन करना आवश्यक

सहकारिता क्षेत्र के डिजीटलीकरण और विस्तार पर केंद्रित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

सहकारी संस्थाओं को डिजीटल रूप से सशक्त बनाने में ऑडिट प्रक्रिया को ऑनलाइन करना आवश्यक

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा रहे शामिल

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 24 अप्रैल : केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को डिजीटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऑडिट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सभी ऑडिट प्रक्रियाएं अब डिजीटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होनी चाहिए। साथ ही निर्देश दिए कि प्रदेश की पैक्स की समस्याओं की पहचान कर उन्हें मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार की जाएं। अन्न भंडारण योजना को भी गति देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री और प्रदेश के सहकारिता मंत्री चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर पत्रिका का विमोचन करते हुए।

ड्रग लाइसेंस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के दिए निर्देश

गुर्जर ने जीवन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए ड्रग लाइसेंस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल केवल 08 केंद्रों को लाइसेंस प्राप्त हुआ है जबकि आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पैक्स को योजना से जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त 09 एफपीओ का पंजीकरण किया जा चुका है। उनकी वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है ताकि उनके व्यापार को विस्तार मिल सके। उन्होंने बैठक में राज्य के सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए कहा कि बैंकों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए। किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर 85 फीसदी तक की गारंटी का लाभ सुनिश्चित किया जाए। पैक्स को माइक्रो एटीएम सुविधा से जोड़कर ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे सहकारिता की भावना जन-जन तक पहुंच सके।

सरकार ने द्वारा निर्धारित 2500 नए पैक्स खोलने का लक्ष्य शीघ्र किया जाना चाहिए पूर्ण

बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 2500 नए पैक्स खोलने का लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। फेडरेशन से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि सभी हितधारकों को समान सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की श्रेष्ठ सहकारी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा में लागू करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने वीटा पार्लर को आधुनिक स्वरूप में विकसित कर शहरी क्षेत्रों की सोसायटियों में स्थापित करने के निर्देश दिए। मंडियों के नियमित निरीक्षण को अनिवार्य मानते हुए उन्होंने कहा कि इससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते हुए प्रदेश की सहकारी प्रणाली को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली 25 सेवाओं को प्रभावी, सरल और निर्बाध रूप से लागू किया जाए ताकि आमजन को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष और सुगम लाभ मिल सके। बैठक में सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, हैफेड के प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक डॉ. राजीव कुमार सहित सहकारिता विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Downloaded from
SAMVAD